भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.08.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2628 का उत्तर

उत्तर कन्नड क्षेत्र में कोंकण रेलवे

2628. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तलगुप्पा से तडस, अंकोला से हुबली और धारवाड़ से बेलगावी रेललाइनों की स्थापना से संबंधित रेलवे परियोजना की प्रगति और स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कोंकण रेलवे उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में कारवार, गोकर्ण, कुमता और मूर्देश्वर स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्थानीय लोगों के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

उत्तर कन्नड क्षेत्र में कोंकण रेलवे के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के अतारांकित प्रश्न सं. 2628 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- **तालगुप्पा-सिरसी-हुबली नई लाइन : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए तडस के रास्ते तालगुप्पा-सिरसी-हुबली नई लाइन (158 किलोमीटर) के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है।**
- **हुबली-अंकोला : हुबली-कीरावति (47 किलोमीटर) खंड में मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्यों को पूरा किया गया है, इसके अतिरिक्त 569.64 हेक्टेयर वन भूमि की वानिकी एवं वन्य जीव मंजूरी न मिलने और संबंधित मुकदमेबाजी के कारण कार्य को निष्पादित नहीं किया जा सका है। अब मुकदमेबाजी के समाधान के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वन्यजीवों को बार-बार होने वाली परेशानियों से बचने के लिए वन क्षेत्र में लाइन की योजना दोहरी लाइन वाली बनाई जानी चाहिए। तदनुसार सभी हितधारकों के परामर्श से दोहरी लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया।**
- **बेलगॉम-धारवाड : कित्तूर के रास्ते बेलगॉम और धारवाड (73 किलोमीटर) के बीच नई लाइन को रेलवे और कर्नाटक राज्य सरकार के बीच 50:50 लागत साझा करने के आधार पर स्वीकृत किया गया है और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कार्य केआईएडीबी (कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड) को सौंप दिया है। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को 888 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए मांगपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से भूमि का कोई भी हिस्सा सौंपा नहीं गया है।**

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित

करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाध्यताओं के बावजूद, परियोजना(परियोजनाओं) को तेजी से पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से, कर्नाटक राज्य में निधि आबंटन और परियोजनाओं के लिए तद्नुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन के संबंध में वृद्धि
2009-14	₹835 करोड़/वर्ष	-
2023-24	₹7,561 करोड़	9 गुना
2024-25	₹7,559 करोड़	9 गुना

कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमिशनिंग निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	कमीशन किया गया औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	565 किमी	113 किमी/वर्ष	-
2014-24	1,633 किमी	163 किमी/वर्ष	लगभग 1.5 गुना

रेल मंत्रालय ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर स्टेशनों तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उसका क्रियान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार, स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को जोड़ने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के तहत 1324 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से कर्नाटक राज्य में स्थित 59 स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किया गया है।

कर्नाटक राज्य में विकास के लिए पहचान की गई स्टेशनों की सूची निम्नानुसार हैः-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
कर्नाटक	59	अलमट्टी, अलनावर, अर्सिकेरे जंक्शन, बादामी, बागलकोट, बल्लारी, बेंगलुरु कैंट, बंगारपेट, बंटावाला, बेलगावी, बीदर,

		बीजापुर, चामराज नगर, चन्नापटना, चन्नासांद्रा, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, डोडबल्लापुर, गडग, गंगापुर रोड, गंगावति, घटप्रभा, गोकक रोड, हरिहर, हसन, होसपेटे, कलबुर्गी, केंगेरी, कोप्पल, क्रांतिविरा संगोल्ली रायन्ना (बेंगलुरु स्टेशन), कृष्णराजपुरम, मल्लेश्वरम, मालूर, मांड्या, मंगलौर सेंट्रल, मंगलौर जं., मुनिराबाद, मैसूरु, रायबाग, रायचुर, रामानगरम, रानीबेन्नूर, सागर जंबगरु, सकलेशपुर, साहाबाद, शिवमोग्गा टाउन, श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन, सुब्रमण्यम रोड, तलगुप्पा, तिप्तुर, तुमकुरु, उडुपी, वाडी, व्हाइटफील्ड, यादगिर, यशवंतपुर, चिकोडी रोड स्टेशन

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए कार्य को मंजूरी देने और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में कारवार, गोकर्ण रोड, कुमटा और मुर्डेश्वर स्टेशनों पर प्रमुख यात्री सुविधाएं और विकास कार्य जैसे प्लेटफॉर्म शेल्टर, फुट ओवर ब्रिज, जैव-शौचालय, प्लेटफॉर्म का विस्तार और सुधार, परिचलन क्षेत्र, नए उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म आदि शुरू किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान इन 4 स्टेशनों के विकास कार्यों के लिए कुल 6.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उपरोक्त यात्री सुविधा और विकास कार्यों के अलावा, अंकोला से शिरूर के बीच संपूर्ण रेलपथ नवीकरण (सीटीआर) का संरक्षा कार्य जिसमें गोकर्ण और मुर्डेश्वर स्टेशनों पर मुख्य लाइन पर

संपूर्ण रेलपथ नवीकरण शामिल है, भी पूरा हो गया है। मुर्डेश्वर में यात्री लूप लाइन का अतिरिक्त यातायात सुविधा कार्य मुहैया कराया गया है।

रेल प्रशासन अर्थात् मंडल कार्यालय, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर माननीय संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा प्राप्त नई गाड़ियों के शुरू करने, मौजूदा गाड़ियों का विस्तार, ठहराव का प्रावधान, नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, ऊपरी/निचले सड़क पुलों आदि के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिसके लिए सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

राज्य सरकार से किसी ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कुमटा के स्थानीय लोगों ने उत्तर कन्नड़ जिले में मिर्जान-कुमटा खंड में समपार-62 के स्थान पर ऊपरि पुल के लिए अनुरोध किया है। कोंकण रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया गया है।

*****